पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 14, अंक 3/2013

शहर के विकास में जनभागीदारी आवश्यक - मनीष पारीक

शहर के सुनियोजित विकास में जन भागीदारी आवश्यक है। जयपुर नगर निगम शहर की मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ जनता का सहयोग लें तो कई समस्याओं का निवारण आसानी से किया जा सकता है।

उक्त विचार जयपुर नगर निगम के उप महापौर मनीष पारीक ने कट्स द्वारा एशिया फाउण्डेशन के सहयोग से संचालित 'माई सिटी' परियोजना के तहत जयपुर में आयोजित एडवोकेसी व प्रचार–प्रसार बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त करते हुए नगर निगम की कार्य प्रणाली में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।

इस अवसर पर परियोजना के तहत कराए गए सर्वेक्षण के प्रमुख तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करते हुए कट्स के अमरदीप सिंह ने बताया कि शहर के 45 फीसदी लोगों का कहना कि उनके क्षेत्र में सड़कें है ही नहीं, यदि हैं तो बहुत बुरी स्थिति में हैं एवं 36 फीसदी लोगों को रात में अंधेरी गलियों से गुजरना पड़ता है। 34 फीसदी लोगों को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता और 14 फीसदी लोग पानी की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है। खास बात यह है कि जयपुर शहर में 52 फीसदी लोग कचरे को खुले में फेंकते हैं, कहीं–कहीं तो यह आंकड़ा 80 फीसदी से भी ज्यादा है, जो जनस्वास्थ्य की दृष्टि से एक गंभीर खतरा है। सर्वे में यह भी सामने आया कि जिन वार्डों में नागरिक विकास समितियां हैं, वहां 80 फीसदी लोग ऐसी समस्याओं से काफी हद तक बचे हुए हैं, जो कि उनकी सक्रियता को प्रदर्शित करता है।

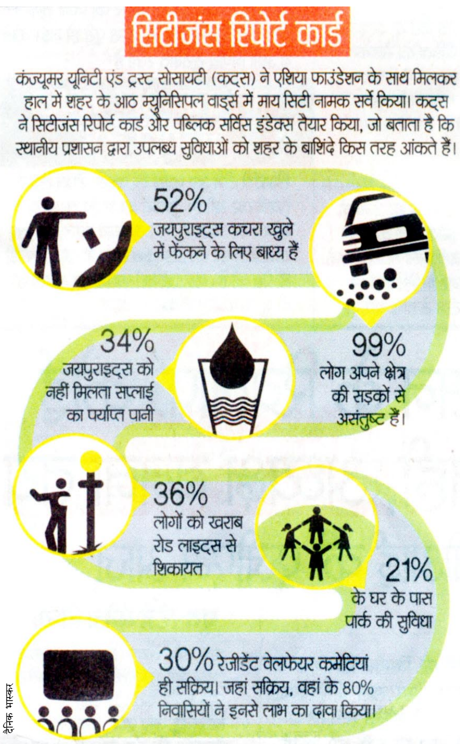

कार्यक्रम की शुरूआत में राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव एम.एल. मेहता ने कहा कि रोजगार की तलाश में गांवों से शहर आने वालों को योजनाओं में नजर अंदाज करने के कारण कच्ची बस्तियों की तादाद बढ़ी है। सही नीतियों के अभाव में स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं निष्क्रिय रही हैं। बैठक में एशिया फाउण्डेशन के डॉ. शोमिखो राहा ने कहा कि भारत में 23 प्रतिशत शहरीकरण है और आने वाले समय में शहरीकरण और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कट्स द्वारा संचालित परियोजना से बहुत सारे ऐसे तथ्य उभरकर सामने आए हैं जो जयपुर शहर की सही तस्वीर पेश करते हैं।

बैठक में जॉर्ज चैरियन, निदेशक, कट्स ने परियोजना के तहत पिछले एक साल में की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने सर्वे में सामने आए परिणामों पर अफसोस जताते हुए कहा कि नागरिक सहभागिता से इन समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। परियोजना के तहत तैयार किए गए 'जन सेवा सूचकांक' के बारे में बताते हुए कट्स के ओम प्रकाश आर्य ने चयनित वार्डों में विभिन्न सेवाओं की स्थिति पर प्रस्तुतिकरण भी दिया।

कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम के कई पार्षदगणों, अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक विकास समितियों व मीडिया के प्रतिनिधियों ने सक्रियता से भाग लिया और अपने अनुभवों व विचारों से अवगत कराया।

इस अंक में...

- बेशुमार दौलत कमाने के लिए राजनीति जरूरी 3
- दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है भ्रष्टाचार 5
- मिला 'राइट टू रिजेक्ट' का अधिकार 7
- पानी व्यर्थ नष्ट करने पर जुर्माना 9
- नहीं लग पाया भ्रूण हत्याओं पर अंकुश 10

जैविक खेती पर कार्यशालाएं आयोजित

कट्स द्वारा कन्ज्यूमर कॉर्डिनेशन कॉउंसिल, स्वीड्स सोसायटी फॉर नेचर कन्जर्वेशन, कन्ज्यूमर इण्टरनेशनल और स्थानीय संस्था आत्मा के सहयोग से संचालित परियोजना के तहत सभी के लिए सुरक्षित एवं सतत भोजन, जैविक खेती पर सितम्बर 2013 में जयपुर के सांभर ब्लॉक की दस ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई। कार्यशालाओं में कट्स के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इन कार्यशालाओं में कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के डॉ. संग्राम सिंह, डॉ. जे.पी.यादव, डॉ. श्रीराम शर्मा, कर्ण नरेन्द्र एवं अन्य संदर्भ व्यक्तियों ने कार्यशाला में उपस्थित ग्रामीणों व किसानों को जैविक खेती के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार जैविक खेती से किसान लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट बनाने व उपयोग के तरीकों के साथ-साथ इससे लाभान्वित होने के तौर तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं किसानों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सन्तोषप्रद जवाब दिया। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इन कार्यशालाओं में जैविक खेती पर बनाए गए पोस्टर का भी विमोचन किया गया।

'कट्स' सर्वेक्षण -2013

प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी राजस्थान के लोगों की पहली पसंद

राजस्थान के 64 फीसदी लोग नरेन्द्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि केन्द्र की वर्तमान यूपीए सरकार के काम-काज से वे संतुष्ट नहीं है। यह तथ्य 'कट्स' द्वारा राजस्थान में कराए गए 'हालात सर्वे, 2013' में सामने आया है।

यह सर्वे चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय व राजस्थान सरकार के काम-काज का आकलन करने और विभिन्न समस्याओं पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के मकसद से, प्रदेश के विभिन्न जिलों के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया गया। सर्वे में राज्य के सभी जाति, समुदाय व वर्गों के लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है।

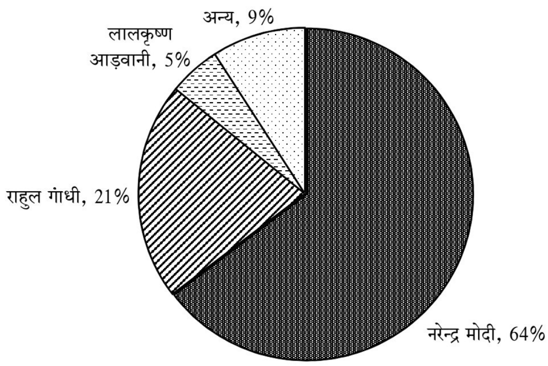

भ्रष्टाचार देश की प्रमुख समस्या

सर्वे के विश्लेषण में यह सामने आया कि प्रदेश के 44 फीसदी लोग भ्रष्टाचार और महंगाई को वर्तमान केन्द्र सरकार की देन मानते हैं। लोगों ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए भ्रष्टाचार, कालाबाजारी व आर्थिक नीतियों की असरदार क्रियान्विति नहीं होने को खास कारण माना है। लोग भ्रष्टाचार को देश की प्रमुख समस्या मानते हैं। लोगों का सोचना है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ रही है।

खाद्य सुरक्षा से मिलेगी भूख से निजात?

खाद्य सुरक्षा आध्यादेश से निर्धन व कमजोर वर्ग को भूख से निजात नहीं दिलाई जा सकेगी, 34 फीसदी लोगों का यह मानना है, जबकि 40 फीसदी लोग मानते हैं कि इससे कुछ हद तक ही गरीबों को फायदा मिल सकेगा। अभी भी 81 फीसदी लोग देश की राशन वितरण व्यवस्था से ही संतुष्ट नहीं है। लोगों का यह भी मानना है कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली निर्धन वर्ग को आगे बढ़ाने के बजाय कमजोर करेगी। लोग काम-धंधे व श्रम से विमुख हो जाएंगे। इसके बजाय गरीबों के लिए शिक्षा, छात्रवृत्ति व रोजगार के लिए ऋण जैसी सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए।

– यह भी आया सामने–

- *राजस्थान के मात्र 21 फीसदी लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं।*
- *केन्द्र सरकार के अब तक के कार्यकाल को प्रदेश के 09 फीसदी लोगों ने सफल, 48 फीसदी ने सामान्य, 41 फीसदी ने असफल बताया।*
- *प्रदेश के 16 फीसदी लोग राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल को सफल, 57 फीसदी सामान्य और 25 फीसदी असफल मानते हैं।*
- *प्रदेश में मुफ्त दवा और जांच योजना से 39 फीसदी लोग संतुष्ट हैं, वहीं 51 फीसदी लोग इसे गुणवत्ता पूर्ण सेवा नहीं मानते।*

भाजपा के बहुमत की उम्मीद

राज्य के लोगों ने राजस्थान विधान सभा में भी परिवर्तन की इच्छा जताई है। प्रदेश के 57 फीसदी लोगों ने वर्तमान राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल को सामान्य दर्जे का माना है। प्रदेश के 64 फीसदी लोगों की अगले मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे पहली पसंद है तथा 61 फीसदी लोगों ने यह उम्मीद जताई है कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा।

राजस्व वसूली में अनियमितता

राज्य सरकार की ढिलाई के कारण करों और गैर करों से होने वाली राजस्व प्राप्तियों में 763.52 करोड़ रुपए की अनियमिताएं सामने आई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 319.57 करोड़ की अनियमितताएं खान विभाग में शामिल है।

यह जानकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ओर से जारी की गई मार्च 2012 तक के लेखा परीक्षण रिपोर्ट से सामने आई है। इससे अनियमितताओं के ऐसे प्रकरण भी सामने आए हैं, जिसमें आम लोगों के स्थान पर निजी कंपनियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए छूटें दी गई हैं, लेकिन सरकार ने कैग की ओर से जानकारी मांगने के बाद भी कारणों का खुलासा नहीं किया। रिपोर्ट में वाणिज्यिक कर, परिवहन कर, स्टांप ड्यूटी, भू राजस्व, स्टेट आबकारी और खान विभाग में होने वाली राजस्व आय के बारे में एक साल के लेखों का परीक्षण किया है। इसमें कई अनियमिताएं सामने आई है। इनका विभागों की ओर से कोई समाधान नहीं हुआ। *(दै.भा., 29.08.13)*

बंट रही है नकदी व मुफ्त उपहार

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त उपहार दिए जाने को निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने वाला बताया है। पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में किए कई ऐसे वादों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद हिल जाती है। इन्हें चुनाव आयोग आचार संहिता के दायरे में लाकर इनका नियमन कर सकता है। राजस्थान में तो चुनाव से पहले ही कई बजट घोषणाओं व योजनाओं के तहत नकद पैसा बांटा जा रहा है।

हालांकि सरकार इन्हें बजट घोषणाएं बताती है, लेकिन बजट घोषणा में साड़ी-कम्बल, स्कूली छात्राओं को साइकिल, मेरिट में आये विद्यार्थियों को टैबलेट जैसे वादों को जल्द पूरा करने के मकसद से नकद पैसा बांटा जा रहा है। अर्थशास्त्री प्रो. सतीष बत्रा का कहना है कि इससे यह सुनिश्चित नहीं है कि बांटा गया नकद पैसा उसी काम में खर्च हो रहा है। *(रा.प., 06.07.13)*

किसी काम की नहीं रही 'गारंटी'

पूरे प्रदेश में 14 नवम्बर 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गांरटी अधिनियम-2011 लागू है। इस कानून में हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। कर्मचारी द्वारा नियत समय पर सेवाएं प्रदान नहीं करने पर उस पर 500 रुपए से 5 हजार रुपए तक की पैनल्टी लगाने का प्रावधान कानून में है। लेकिन आम जन को राहत देने के लिए सरकार ने भले ही निर्धारित अवधि में काम पूरा होने की गारंटी देने वाला यह कानून 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' लागू कर दिया हो, लेकिन नौकरशाही के ढुलमुल रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोगों को टरकाने वाला उनका पुराना अंदाज आज भी कायम है।

ज्यादातर दफ्तरों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन ही स्वीकार नहीं किए जाते। यदि किसी दबाव के चलते आवेदन ले भी लिए जाते हैं तो आवेदक को चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब लोक सेवा गारंटी अधिनियम में काम की गारंटी नहीं है। प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में 1,19,109 आवेदन लम्बित हैं। *(रा.प., 18.07.13)*

माही नहर के टेंडर में घपला

बागीदौरा क्षेत्र के नोन कमांड एरिया में बन रही हरिदेव जोशी साइफन बैरल में एक करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है। प्रकरण के अनुसार साइफन बैरल बनाने के 376 लाख रुपए के काम के लिए जल संसाधन विभाग जयपुर के अतिरिक्त अभियंता ने निविदाएं आमंत्रित की थी। इसमें दो निविदाएं ही आई।

माही बांध खंड प्रथम के एक्सईएन आरएस भदौरिया ने बिना निविदा खोले एक फर्म को डिसक्वालीफाई कर अहमदाबाद की एक फर्म एमएस हार्डवेयर टूल्स एंड मशीनरी का टेंडर 43 प्रतिशत ऊंची दर पर पास कर दिया। यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई अधिकारियों ने कंपनी से मिलीभगत कर 367 लाख के टेंडर को 499 लाख रुपए कर दिया। मामले की एसीबी जांच में 1.01 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें कई आला अफसर फंसे हैं। *(दै.भा., 30.07.13)*

सड़क सुरक्षा पर नहीं हुआ खर्च

राज्य में सड़क यातायात को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए वर्ष 2012-13 के लिए रोड सेफ्टी काउंसिल को पांच करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे लेकिन उनमें से खर्च किए गए सिर्फ 75 लाख 79 हजार रुपए। इनमें से भी 29 लाख 43 हजार रुपए मुख्यमंत्री के संदेश प्रसारित करने व विज्ञापनों पर खर्च किए गए।

विधायक ओम बिड़ला का कहना है कि सरकार ने जो राशि पांच करोड़ तय की, उसका 20 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाई। जो राशि खर्च हुई, उसमें भी विज्ञापन पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। अगर राशि का बेहतर उपयोग होता तो दुर्घटनाएं बड़ी संख्या में घट सकती थी। सरकार को सड़कों पर चलने वाले आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। *(रा.प., 22.09.13)*

नहीं बांटी करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति

राजधानी के हजारों गरीब छात्रों को 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की छात्रवृत्ति नहीं बंटी। वर्ष 2010 से 2013 के तहत गरीब छात्रों के लिए राजकोष से छात्रवृत्ति की राशि तो जारी हुई, पर कई चक्कर लगाने के बावजूद छात्रों को यह राशि नहीं बांटी गई।

मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का है। थक-हारकर छात्रों ने अपनी पीड़ा विभाग के आयुक्त अजिताभ शर्मा तक पहुंचाई। तब कहीं जाकर मामले की परतें खुली और विभागीय जांच कमेटियां बनाकर जांच की। जांच में दोषी पाए गए दो अधिकारियों को एपीओ भी किया गया। इसके बाद आयुक्त अजिताभ शर्मा के प्रशिक्षण हेतु मसूरी जाते ही पीछे से इन अधिकारियों को न केवल बहाल किया गया बल्कि उन्हें जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण ओहदे पर बिठा दिया गया।

(रा.प., 03.08.13)

बेशुमार दौलत कमाने के लिए राजनीति जरूरी

बेशुमार दौलत कमाने के लिए राजनीति अच्छा व्यवसाय बनता जा रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट इस सच्चाई को बयां करती है। 2004 से अब तक जितने विधायक और सांसद दोबारा चुनाव जीते, उनकी संपत्ति ज्यादा बढ़ी। जितनी तेजी से राजनीति में अपराधियों का बोलबाला बढ़ा रहा है, उतनी ही तेजी से ऐसे राजनीतिज्ञों की संपत्ति भी बढ़ रही है।

अपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने में सभी पार्टियां एक जैसी हैं। धीमी न्याय व्यवस्था के कारण ऐसे जनप्रतिनिधियों के मामले काफी अरसे से लंबित हैं।

(रा.प., 30.07.13)

कैसे होंगे खर्च तीस हजार करोड़?

चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए 40 हजार 139 करोड़ रुपए की भारी भरकम वार्षिक योजना तो बना ली, लेकिन इस बार पूरी राशि खर्च होना मुश्किल लग रहा है। हकीकत यह है कि एक अप्रेल से लेकर जुलाई तक करीब 10 हजार 300 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके हैं। ऐसे में वित्त वर्ष के शेष आठ महीनों में 29 हजार 831 करोड़ रुपए खर्च किया जाना बच रहा है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि चुनावी वर्ष में अक्सर शुरुआती तीन-चार महीनों में राशि तेजी से खर्च होती है। लेकिन बाद में आचार संहिता, चुनाव प्रक्रिया और नई सरकार के गठन में तीन से चार महीने बेहत सुस्त रफ्तार से काम चलता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस अवधि में करीब 15 प्रतिशत राशि खर्च हुई थी। इस बार चुनावी वर्ष होने से इस अवधि में खर्च की रफ्तार तेज है। बाद में वर्ष के आखिरी दिनों में राशि खर्च कर खानापूर्ति कर ली जाएगी।

(रा.प., 16.09.13)

विदेशी मदद वाली योजनाओं में सुस्ती

प्रदेश के विकास के लिए विदेशी मदद से चल रही परियोजनाएं सरकारी सुस्ती का शिकार हो रही हैं। कुछ योजनाओं की तो ऐसी स्थिति है जिनमें आठ साल बीतने पर भी आधी रकम खर्च नहीं हो पाई। विदेशी मदद से प्रदेश में फिलहाल आठ परियोजनाएं चल रही हैं।

इनमें नगरीय विकास, कृषि, सिंचाई, गरीबी उन्मूलन, पेयजल वितरण, ग्रामीण आजीविका व वानिकी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी लागत में लगभग 70 से 75 फीसदी राशि विदेशी ऐजेन्सियों और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाती है। लेकिन कड़ी मॉनिटरिंग के अभाव में इनका लाभ राज्य को ढंग से नहीं मिल पाया।

(रा.प., 20.09.13)

कच्ची बस्ती के सवा अरब अपात्रों पर खर्च

जयपुर कच्ची बस्ती के विकास के नाम पर राज्य सरकार ने आठ साल के दौरान प्रदेश में 123 करोड़ रुपए उस जगह खर्च कर दिए, जहां जरूरत ही नहीं थीं। जो कच्ची बस्तियां नहीं थी वहां पानी की तरह पैसा बहाया गया।

वर्ष 2005 से 2012 के बीच की गई इस गड़बड़ी का खुलासा किया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत मिली राशि में से 7719 अपात्र लोगों के लिए आवास निर्माण पर 37.55 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए।

रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्र ने आईएचएसडीपी के तहत राज्य के 45 शहरों की 48 परियोजनाओं के लिए 653.33 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इनमें से 123.43 करोड़ रुपए उन बस्तियों पर खर्च कर दिए, जिन्हें वर्ष 2001 की जनगणना में कच्ची बस्ती नहीं माना गया था।

(रा.प., 31.08.13)

मिट्टी हो गए 20 हजार करोड़

पिछले पांच साल के दौरान मनरेगा में आठ लाख से ज्यादा कामों पर 20 हजार 566 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए, लेकिन इससे प्रदेश में कहीं भी स्थाई परिसंपत्तिया खड़ी नहीं हुई। यह पूरा पैसा मिट्टी से जुड़े कामों और मजदूरी में लगा। यह चौंकाने वाली जानकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट में दी गई है, जो विधान सभा में पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मनरेगा कानून के तहत आने वाले धन को सरपंचों, अफसरों और प्रशासनिक अमले के बाकी लोगों ने किस तरह लूटा।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने अपना अंश देरी से जारी किया। सरपंचों को अनधिकृत अग्रिम पैसा जारी कर दिया गया। सामग्री खरीदने के वित्तीय प्रावधान ही नहीं थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सरपंचों व सचिवों ने सामग्री भी खरीद ली। ऐसे काम करवा दिए गए जो कानून के तहत होने ही नहीं थे। पंचायतों ने खर्च का न तो पूरा हिसाब-किताब रखा और न ही प्रावधान के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण ही करवाया।

(दै.भा., 28.08.13)

सड़क ठेकेदारों पर जेडीए मेहरबान

नियम कायदों को ताक पर रख कर जेडीए सड़क ठेकेदारों पर मेहरबान है। बदहाल सड़कों के पेचवर्क करने व नवीनीकरण तक में उनकी मनमानी जारी है। हालात यह है कि जो सड़क क्षेत्र दोषपूर्ण दायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी) अवधि में है, उसी पर डामर की परत चढ़ाने के लिए जेडीए ने 12 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। जबकि, अनुबन्ध के तहत ठेकेदार को तीन साल तक सड़क सुधार का काम करना है, जिसकी मियाद अगले साल पूरी होगी।

मसलन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से ठीक पहले (जनवरी 2012) जेडीए ने ट्रांसपोर्ट नगर से कुण्डा तक (दिल्ली रोड) नवीनीकरण, पेचवर्क व अन्य सुधार की आड़ मे ठेकेदार को 12 करोड़ रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई।

(रा.प., 24.09.13, 25.09.13)

आवासन मण्डल में करोड़ों की अनियमितता

आवासन मण्डल के अफसरों की वजह से वर्षों तक सरकारी खजाने को चपत लगती रही। मण्डल प्रशासन की मेहरबानी के चलते करोड़ों रुपए की अनियमितताएं हुई और कई जिम्मेदार एवं दोषी अफसर रिटायर भी हो गए। अब इन अनियमितताओं के खुलासा होने पर मण्डल को जवाब देते नहीं बन रहा।

इन अनियमिताओं का खुलासा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने किया है। विभाग ने ऑडिट में अ श्रेणी जो सरकारी खजाने को नुकसान की है, उसमें 96 मामलों पर सवाल उठाया है जिसमें करीब 143 करोड़ रुपए की अनियमितताएं है। ब श्रेणी के 80 मामलों में 200 करोड़ रुपए की अनियमितताएं हैं। इनमें से कई मामले 23 वर्ष पुराने भी हैं। मण्डल प्रशासन अब इन सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं होने से कई अफसर रिटायर हो गए हैं। *(रा.प., 30.07.13)*

चार पायदान नीचे खिसका प्रदेश

राजस्थान की विकास दर पिछले वर्ष के मुकाबले 2012-13 में 0.80 प्रतिशत की गिरावट आई है और प्रदेश 16वें से 20वें स्थान पर चला गया है। हाल ही केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) की ओर से जारी राज्यों की विकास दर के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार राज्य की विकास दर करीब 5.31 प्रतिशत रही है।

स्थाई रूप से इसकी वास्तविक जानकारी मार्च, 2014 तक मिलेगी। यह पिछले वर्ष 6.11 प्रतिशत थी। राजस्थान की औसतन विकास दर पिछले 10 वर्षों में लगभग 6.5 से 7.0 प्रतिशत रही है। *(रा.प., 25.09.13)*

करोड़पति निकला इंजीनियर

कृषि कनेक्शन चालू करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधीक्षण अभियंता जयपुर ग्रामीण के आदर्श नगर स्थित आवास की तलाशी में पत्नी के नाम बिजली के खंभे बनाने की फैक्ट्री के दस्तावेज, फार्म हाउस, प्लॉटस, जेवरात के अलावा 42.70 लाख रुपए नकद मिले हैं।

इस सम्पत्ति की कीमत करोड़ों रुपए हैं। आईजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार लिपिक राम किशोर से पूछताछ व जांच में एनआरआई डॉ. अभिनव वर्मा की कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन की फाइल पास करवाने में सुरेन्द्र की भूमिका सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। सुरेन्द्र के आवास से मिली डायरी में रिश्वत लेने का हिसाब-किताब दर्ज है। इसकी जांच के बाद अन्य लोगों से भी पूछताछ होगी। मूल्यांकन के बाद आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा दर्ज होगा। *(रा.प., 09.08.13, 10.08.13)*

भ्रष्टाचारी को बचाने के खातिर दी रिश्वत

घूसखोरी में बन्द थानेदार भाई को बचाने की खातिर गवाह को 50 हजार रुपए की रिश्वत दे रहें एईएन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दबोच लिया। गिरफ्तार एईएन अरविन्द मीणा के भाई बृजेश मीणा ने पिछले साल अलवर में थानेदार रहते आसाम के व्यापारियों से साढ़े छह लाख रुपए की रिश्वत ली थी।

एसीबी अफसरों के मुताबिक परिवादी जगदीश प्रसाद शर्मा को कई दिनों से बयान बदलने के लिए लालच और धमकी दी जा रही थी। उसने इसकी शिकायत एसीबी के एडीजी अजीत सिंह से की। योजना के अनुसार जगदीश के बुलाने पर अरविन्द मीणा होटल पहुंचा और जगदीश को बयान समझाने के बाद रिश्वत के 50 हजार रुपए उसे दिए। इसी दौरान एसीबी ने अरविन्द और उसके सहयोगी मानसिंह मीणा को रिश्वत देते गिरफ्तार कर लिया। अरविन्द जयपुर डिस्कॉम के जमवारामगढ़ जीएसएस पर जेईएन के पद पर हैं। *(रा.प. एवं दै.भा., 06.07.13)*

वापस ले सकेंगे रिश्वत की राशि

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में पिछले दिनों बनाए गए 'रिवाल्विंग फण्ड' के इस्तेमाल की सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी है। एसीबी के एडीजी अजीत सिंह ने बताया कि यह प्रावधान किया जाएगा कि मामले में चालान पेश होने तथा गवाही के बाद रिश्वत की राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिवादी से अण्डरटेकिंग ली जाएगी कि अदालत का फैसला आने के बाद जब्त रकम मिलने पर वह राज्य सरकार को जमा करा देगा। उन्होंने बताया कि पिछले दो साल से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने में हम अव्वल रहे हैं। *(रा.प., 17.07.13)*

दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है भ्रष्टाचार

भारत में भ्रष्टाचार विश्व की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। विश्व में 27 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत देकर अपना काम कराया है, जबकि अकेले भारत में 54 फीसदी लोगों ने रिश्वत दी है। यानि हर दो में से एक व्यक्ति ने यह माना है कि उसने रिश्वत दी है।

ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की ओर से किए गए सर्वेक्षण में यह सामने आया है। सर्वे में 40 फीसदी भारतीयों ने स्वीकार किया है कि भारत में भ्रष्टाचार सच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्ट संस्थानों में राजनीतिक दलों का नंबर रहा है। देश में 75 फीसदी लोगों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया है। करीब 47 फीसदी लोगों ने भ्रष्टाचार को एक बहुत गंभीर समस्या मानते हुए कहा कि इसका निदान बहुत जरूरी है। *(दै.भा. एवं न.नु., 10.07.13)*

तेरह साल में बनाई करोड़ों की प्रापर्टी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिरसी रोड, जयपुर स्थित शाखा में कार्यरत अफसर लक्ष्मण प्रसाद कायल के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली। इस पर ब्यूरो अधिकारियों की टीम ने वैशाली नगर स्थित उनके मकान और उदयपुरवाटी स्थित पैतृक मकान पर छापा मार कर तलाशी ली। इन दोनों जगह से कुल 45 भूखण्ड के दस्तावेज बरामद और हुए हैं। साथ ही तीन बैंक लॉकर भी मिले।

जयपुर में स्थित इन भूखण्डों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया कि कायल बैंक सेवा में 13 साल पहले ही आए थे। इतने से समय में उन्होंने कहां से इतनी प्रापर्टी में निवेश किया। इस पर ब्यूरो अधिकारियों ने उसके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज किया है। *(रा.प., 20.09.13)*

लालच में लगाई नई नौकरी दाव पर

राज्य सरकार के सेवा नियमों में साफ है कि परिवीक्षा काल यानि प्रोबेशन पीरियड के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में फंसने पर नौकरी जा सकती है। इसके बावजूद नए सरकारी अधिकारी-कर्मचारी मामूली रकम के लिए नौकरी दाव पर लगा रहे हैं। इसका सबूत पिछले दिनों हुई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक कार्रवाई में सामने आया है। ब्यूरो ने पिछले आठ महीनों में ही एक आरएएस, तीन कनिष्ठ अभियंताओं और एक वाणिज्य कर अधिकारी को घूस लेते गिरफ्तार किया।

इनमें से किसी ने पांच हजार, किसी ने छह हजार, तो किसी ने बारह हजार रुपए की रिश्वत ली और फंस गए। जयपुर विकास प्राधिकरण के जेईएन मुकेश कुमार सैनी, कनिष्ठ अभियंता शीना गुप्ता, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी श्रीमती मुदगल और आबू रोड़ पंचायत समिति की कनिष्ठ अभियंता प्रियंका मीणा इसके हालिया उदाहरण हैं। *(रा.प., 18.08.13)*

पक्के चोर संसद व विधानसभाओं में

जैन मुनि तरुण सागर ने कहा है कि राजनीति में जो कच्चे चोर हैं, वे पकड़े जाते हैं और जेलों में बैठे हैं। सत्ता में रहे पक्के चोर बच जाते हैं, वे लोकसभा और विधानसभाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ गरजते हैं और कानून बनवाने में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन्होंने छोटी-छोटी चोरियां की वे छोटे व्यापारी हो गए, जिन्होंने बड़ी चोरियां की, वे बड़े व्यापारी। जिन्हें मौका नहीं मिला वे तथाकथित ईमानदार हो गए।

उन्होंने कहा कि चोर दो तरह के होते हैं। पक्के चोर और कच्चे चोर। कुछ तिहाड़ में हैं। ये सब कच्चे चोर हैं। पर बहुत सारे अभी भी विधानसभाओं और लोकसभा में बैठे हैं, क्योंकि वे पक्के चोर हैं। *(दै.भा., 24.07.13)*

कम्पाउंडर ने 9 साल में बनाए 200 करोड़

नर्सिंग कॉलेज रिश्वत प्रकरण में फंसे आईएनसी सदस्य कम्पाउंडर महेश चन्द शर्मा ने 9 साल में करीब 200 करोड़ रुपए बनाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसके बैंक खातों, लॉकरों को तलाशा तो उनमें बड़ी मात्रा में नगदी, स्वर्णाभूषण और प्रापर्टी के कागजात बरामद किए गए हैं। 1984 में मेडिकल शिक्षा विभाग में नर्स ग्रेड सेकंड के पद पर नियुक्ति पाने वाला यह व्यक्ति विभाग के अफसरों और नेताओं से मिलीभगत कर 2003 में नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरार के रूप में लगा और यहीं से गैर वाजिब तरीके से करोड़पति बनने के सफर की शुरूआत की।

'गिव एंड टेक' का सौदा कर महज दो सालों में वह इंडियन नर्सिंग काउंसिल के राजस्थान का आब्जर्वर बन बैठा। वह 2011 तक इस पद पर रहा। इस दौरान राजस्थान के सभी नर्सिंग कॉलेजों से आईएनसी, एनओसी से लेकर अन्य सभी कामों के लिए एकमात्र ठेकेदार बन बैठा। वह कई कॉलेजों का मालिक बन गया।

रिश्वतखोरी व अनियमितताओं के उसके खिलाफ एसीबी, आईएनसी में हुई शिकायतों के बावजूद वह 2008 में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। घूस लेते पकड़ में आने के बाद उसने मामले में आईएनसी के अध्यक्ष टी. दिलीप कुमार को शामिल बताया। एसीबी ने उनके कार्यालय से भी 70 बोरे दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। *(रा.प. एवं दै.भा., 03.07.13, 04.07.13)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
पाली	मदनलाल माली	अध्यक्ष, नगरपालिका, जैतारण	23,000	दै.भा. एवं रा.प., *02.04.13*
उदयपुर	अजय मेहता	वरिष्ठ प्रोजेक्ट ऑफीसर, हाउसिंग बोर्ड, उदयपुर	30,000	दै.भा., *11.07.13*
डूंगरपुर	खेमेश्वर जोशी	हलका पटवारी, पारड़ा ईटीवार, आसपुर	10,000	दै.भा., *16.07.13*
जयपुर	पूजा शर्मा	नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , सांगानेर, जयपुर	3,000	रा.प. एवं दै.भा., *17.07.13*
जयपुर	राम प्रकाश शर्मा	पटवारी, ग्राम पंचायत मरवा, दूदू	6,000	दै.भा., *17.07.13*
जयपुर	हरिकिशन गौड़	थाना प्रभारी, मुहाना थाना, जयपुर	1,00,000	रा.प. एवं दै.भा., *17.07.13*
उदयपुर	डॉ. अंजली सेठी	सर्जन, एम.बी. अस्पताल, उदयपुर	4,000	दै.भा., *18.07.13*
जयपुर	मुकेश कुमार सैनी	कनिष्ठ अभियंता, जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-8	6,000	दै.भा. एवं रा.प., *22.07.13*
जयपुर	राजेन्द्र सिंह चौहान	कनिष्ठ लिपिक, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	2,000	रा.प. एवं दै.भा., *23.07.13*
जयपुर	श्रीराम शर्मा	पटवारी, थापराली ग्राम पंचायत, आमेर	1,00,000	रा.प. एवं दै.भा., *28.07.13*
जैसलमेर	मोहन लाल	थाना प्रभारी, फलसूण्ड थाना, जैसलमेर	20,000	रा.प., *01. 08.13*
जयपुर	रामकिशोर शर्मा	वरिष्ठ लिपिक, जयपुर डिस्कॉम, खण्ड प्रथम, जयपुर	10,000	दै.भा., *08.08.13*
जैसलमेर	सज्जन सिंह भाटी	शाखा प्रबंधक, जैसलमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक	5,000	रा.प., *10.08.13*
करौली	नसीम खान सहीराम गुर्जर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोडाभीम उपखण्ड, करौली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय	5,000	रा.प. एवं दै.भा., *13.08.13*
राजसमंद	बीना लोठ अब्दुल कादिर	थाना प्रभारी, महिला थाना, राजसमंद पति, बीना लोठ	15,000	दै.भा. एवं रा.प., *17.08.13*
राजसमंद	जमना शर्मा	प्रधानाध्यापिका, राज. प्रा. स्कूल रापडिया, कुंभलगढ़	10,000	दै.भा., *18.08.13*
कोटा	राणाराम	सहायक जेलर, उपकारागृह, रामगंजमंडी	7,000	दै.भा., *12.09.13*
भीलवाड़ा	रामेश्वरलाल झंवर	अतिरिक्त लोक अभियोजक, न्यायालय भीलवाड़ा	8,000	रा.प., *14.09.13*
चूरू	राजेश मील	एसटीओ, वाणिज्य कर विभाग, राजगढ़ चूरू	30,000	रा.प. एवं दै.भा., *14.09.13*
भरतपुर	प्रीतमसिंह	सचिव, ग्राम पंचायत अंधियारी, भरतपुर	12,000	दै.भा., *16.09.13*
राजसमंद	डॉ.जितेन्द्र कुमार	प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ़	5,000	दै.भा., *19.09.13*
भीलवाड़ा	लक्ष्मीनारायण	एएसआई, कोतवाली थाना, भीलवाड़ा	50,000	दै.भा., *21.09.13*
श्रीगंगानगर	सुमन चौधरी	संयुक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, बीकानेर कार्यालय	15,000	रा.प., *25.09.13*
जयपुर	शिवाजी साही	पटवारी, शिवदासपुरा व बम्बोरी हल्का, जयपुर	1,000	दै.भा., *26.09.13*

वोट की गारंटी के लिए खाद्य सुरक्षा

देश में चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए केन्द्र की यूपीए सरकार गरीबों को सस्ता भोजन परोसने जा रही है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विधेयक पर आध्यादेश को मंजूरी दी गई है। आध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के भी हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके लागू होने पर देश के 80 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। गरीबों को सस्ती दरों पर 5 किलो अनाज एक से तीन रुपए किलो के दाम पर मिलेगा।

इसे सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जैसे 2009 में मनरेगा से चुनावी वैतरणी पार करने में मदद मिली थी, इस बार खाद्य सुरक्षा कानून उसे सहारा देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में इस योजना को दो अक्टूबर से ही शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां हैं।

(रा.प., 04.07.13 दै.भा.29.09.13)

मुफ्त दवा योजना होगी देश में लागू

हर आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए भारत सरकार राजस्थान की निःशुल्क दवा योजना मॉडल को पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन इंडिया ऑफिस एवं पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश के 113 सरकारी अस्पतालों का अध्ययन किया जा चुका है।

अध्ययन में शामिल अधिकारियों के मुताबिक 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अध्ययन में शामिल अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ फ्रेंस स्टेबलोर ने कहा कि दवा की परख, खरीद, आपूर्ति से उपलब्धता तक बेहतर समन्वय आवश्यक है। रिपोर्ट अंतिम रूप से डब्लूएचओ को पेश की जाएगी। *(रा.प., 04.09.13)*

सबसे कम बैठकों का रिकार्ड

तेरहवीं विधानसभा में सबसे कम बैठकें करवाने के मामले में राज्य में अब तक गठित हुई पिछली 12 विधानसभाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौजूदा विधानसभा प्रदेश के संसदीय इतिहास में 104 बैठकों के साथ सबसे कम बैठकों के लिए जानी जाएगी। विधायक हर साल 20-25 बार ही लोकतंत्र की जाजम पर बैठे। चुनाव से पहले होने वाला सत्र भी काफी छोटा होगा।

नियमानुसार विधानसभा में प्रति वर्ष 3 सत्र बुलाए जाने जरूरी होते हैं। एक सत्र के खत्म होने के बाद अगला सत्र छह महीनों के भीतर बुलाया जाना जरूरी होता है। प्रति वर्ष न्यूनतम 60 बैठकें होनी चाहिए। लेकिन इस विधानसभा ने 104 बैठकें की है, उनमें से भी 64 दिन हंगामें और स्थगित होने की अवधि के दौरान बीते हैं। शायद 6 महीने में सत्र बुलाने की संवैधानिक बाध्यता नहीं हों, तो बैठकें इससे भी कम रहतीं।

(रा.प., 20.08.13)

'आधार' जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। न्यायाधीश बीएस चौहान व न्यायाधीश एसए बोबड़े की खंडपीठ ने कहा केन्द्र व राज्य सरकारें आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने से पहले आधार प्रस्तुत करने के लिए जोर नहीं दे सकती।

केन्द्र व राज्य सरकारों ने विवाह पंजीकरण, वेतन भुगतान और भविष्यनिधि जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने पर जोर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केएस पुत्तास्वामी की जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि गैर कानूनी अप्रवासियों को आधार कार्ड जारी नहीं किए जाएं, क्योंकि यह उनके प्रवास को वैध बना देगा। लेकिन केन्द्र सरकार अब आधार कार्ड को कानूनी दर्जा देने की तैयारी में लगी है।

(रा.प., 24.09.13, 25.09.13)

अब नहीं हो सकेगा दागियों का बचाव

सजायाफ्ता और दागियों की सदस्यता खत्म करने और उन्हें चुनाव में खड़ा नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, दागी सांसदों व विधायकों को बचाने, जेल में रहते चुनाव लड़ सकने के लिए केन्द्र सरकार ने जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव के लिए किए गए संशोधन आध्यादेश पर कैबिनेट की मुहर लगा दी गई। इसे जल्दबाजी में राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भी भेजा गया। भाजपा नेताओं ने इसका विरोध किया।

नाखुश राष्ट्रपति ने इस पर सफाई मांगी। इसके साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आध्यादेश को बकवास बताते हुए फाड़ फेंकने की सलाह दे डाली। इस पर विचार कर केन्द्र सरकार को आनन-फानन में अपने ही अध्यादेश को वापिस लेना पड़ा। राजनीति में यह एक शुभ संकेत है। अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अमल पर कवायद शुरू करनी होगी। *(रा.प., 27.09.13, 28.09.13)*

भूमिहीनों को जमीन देने की तैयारी

केन्द्र सरकार भूमिहीनों और गरीबों को जमीन देने की तैयारी कर रही है। इस मुहिम से जुड़ी एकता परिषद के साथ मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए नीति बनाने में जुटा है। इस नीति के लागू होने से इसका लाभ आदिवासियों, भूमिहीन किसानों व मजदूरों को मिलेगा। उन्हें यह जमीन खेती और आवास निर्माण दोनों के उद्देश्य से दी जा सकेगी।

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ राजस्थान को भी मिलेगा। जमीन का आवंटन घर की महिला के नाम से किया जाएगा। प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कोशिश यह की जा रही है कि इस पर केबिनेट की मंजूरी ले ली जाए। *(रा.प., 18.07.13)*

मिला 'राइट टू रिजेक्ट' का अधिकार

चुनाव सुधारों की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि मतदाताओं को नेगेटिव वोट डालकर सभी उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार है। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश पी.सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बैंच ने चुनाव आयोग को एवीएम मशीन में उम्मीदवारों की लिस्ट के आखिर में नोटा यादि 'उक्त में से कोई नहीं' के विकल्प का बटन देने को कहा है।

जिन स्थानों पर मतपत्रों से चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, वहां मतपत्रों में यह विकल्प सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गैर सरकारी संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर दिया है।

(रा.प.एवं दै.भा., 28.09.13)

सांभर में लगेगा सोलर प्लांट

खारे पानी को लेकर प्रसिद्ध सांभर झील अब राजस्थान को ऊर्जा व पर्यटन क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। सांभर साल्ट लिमिटेड (एसएसएल) की पहल पर आधा दर्जन से भी अधिक कंपनियों ने झील किनारे अनुपयोगी भू भाग पर 4000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की योजना तैयार की है। इस योजना पर केन्द्र ने भी मुहर लगा दी है। एसएसएल कंपनी हिन्दुस्तान साल्टस लि. की सहयोगी और केन्द्र व राज्य सरकार की साझा कंपनी है।

यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। इसके साथ ही आस-पास के इलाके को विभिन्न तरह के हेरिटेज हब के रूप में विकसित करने की भी योजना है, जिससे देशी-विदेशी पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। योजना के प्रथम चरण में एक हजार मेगावाट का प्लांट लगाया जाना है। जिस पर करीब 7.5 हजार करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। यह 2016 के अंत तक शुरू हो जाएगा।

(दै.भा, 19.08.13 एवं रा.प., 22.09.13)

बिजली चोरों को छूट से लगी चपत

कंगाली से जूझ रही बिजली कंपनियां एक ओर मनमर्जी से बिल थमाकर आम उपभोक्ताओं की जेब काटने में लगी हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव में बिजली चोरों को खुली छूट मिल गई है। राज्य सरकार ने चुनाव के मद्देनजर मौखिक आदेश देकर बिजली चोरी पर कार्रवाई कम करने को कहा, तो कंपनियों ने फील्ड में विजिलेंस चैकिंग बिल्कुल बन्द सी कर दी है।

बिजली कंपनियों की ओर से राज्य सरकार को बतौर जुर्माना वसूली गई राशि की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक पहली तिमाही में जुर्माने से सिर्फ साढ़े तीन करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई है, जबकि पिछले साल एक माह में ही इतनी वसूली हो गई थी। बिजली चोरी की जुर्माना राशि में आ रही गिरावट का खमियाजा आम उपभोक्ता को भुगतना होगा।

(रा.प., 31.08.13, 14.09.13)

सौर व पवन ऊर्जा में प्रदेश होगा अव्वल

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने कहा है कि आज पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व में पांचवें स्थान पर है। उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे वह दिन दूर नहीं जब यह राज्य देश में अव्वल होगा।

उन्होंने जयपुर स्थित बिड़ला ऑडीटोरियम में सौर ऊर्जा पंप पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही। सौर ऊर्जा के विकास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया के अन्य देशों में हमारे लोग सूर्य से बिजली पैदा करने की तकनीक की जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य के 32 किसानों को सौर ऊर्जा पम्प सरताज पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कहा कि प्रदेश में इस योजना की उपलब्धि अग्रणी है। इसके लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी।

(न.नु., 23.08.13)

चुनाव के बाद झेलनी होगी कटौती !

विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश की जनता को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। चुनावी साल में कृषि और घरेलू नए कनेक्शनों की भरमार के चलते बिजली की मांग अगले साल जनवरी में रोजाना दो हजार लाख यूनिट को पार कर देगी, जो अब तक का रिकॉर्ड होगा।

बिजली कंपनियां हर साल करीब 30-40 हजार कृषि कनेक्शन जारी करती है जो इस बार दिसम्बर तक 60 हजार कनेक्शन जारी किए जाएंगे। ऐसी हालत में राजस्थान लोड डिस्पेच सेन्टर (एसएलडीसी) के आकलन के अनुसार करीब 100 से 200 लाख यूनिट बिजली की कमी रहेगी, जिसकी भरपाई नहीं होने पर कटौती ही एक मात्र जरिया होगी।

(रा.प., 05.07.13)

सलाह के नाम लाखों का खर्चा

करोड़ों रुपए का घाटा बता कर हर साल बिजली के दाम बढ़ाने वाली बिजली कंपनियां खरीद-फरोख्त की सलाह के नाम पर सालाना 60 लाख रुपए लुटाने की तैयारी में है। बिजली की 'फोरकास्टिंग' के लिए मुम्बई की एक फर्म को बतौर सलाहकार काम सौंपा गया है।

फर्म विशेषज्ञों की मदद से एक दिन पहले प्रदेशभर में हर 15 मिनट के अंतराल पर विद्युत भार का आकलन कर बिजली व्यवस्था के लिए अभियंताओं को सलाह देगी, जिसकी ऐवज में उसे हर माह पांच लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके हिसाब से विद्युत मांग के तहत बिजली की खरीद-फरोख्त की जाएगी।

(रा.प., 01.09.13)

सुरक्षित नहीं पवन ऊर्जा संयंत्र

राज्य के पवन ऊर्जा उत्पादक संयंत्र अब सुरक्षित नहीं हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था की खामी के कारण ऐसा हो रहा है। जैसलमेर जिले के पवन ऊर्जा उत्पादकों के यहां से केबल और मशीनरी चोरी होने की घटनाएं पिछले तीन महीनों से बढ़ती जा रही है। ऊर्जा उत्पादकों के यहां से अब तक करीब 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की केबल और मशीनरी चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं होने से चोरों की हिम्मत बुलंदी पर है।

कुछ कंपनियों ने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की लेकिन चोरों के आधुनिक हथियारों से लेस होकर आने से उनके सुरक्षाकर्मी भी असहाय रहे हैं। इससे पुराने निवेशक भागने को तैयार बैठे हैं और नया निवेश भी मुश्किल में है।

(न.नु., 24.08.13)

सीएफएल की पन्द्रह माह की गारंटी

मुख्यमंत्री बिजली बचत लैम्प योजना के तहत पन्द्रह माह में सीएफएल खराब हो गई तो उपभोक्ता को नई सीएफएल दी जाएगी। उपभोक्ता को खराब सीएफएल सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करानी होगी। वहां अभियंता उपभोक्ता के बिल से सीएफएल आपूर्ति की जांच करेंगे और नई सीएफएल देंगे। योजना के तहत प्रदेश के सभी 73 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीएफएल दी जानी है, इनमें से 50 लाख उपभोक्ताओं को ये मिल चुकी है।

(रा.प., 16.09.13)

बिजली छीजत, बिजली चोरी ! उपभोक्ता पर है दोनों भारी !!

बिजली की तरह तय होंगी पानी की दरें

राज्य में जल्द ही जल विनियामक प्राधिकरण बनेगा। यह प्राधिकरण राज्य की कृषि, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए पानी की दरें तय करने का काम करेगा। राज्य विधानसभा में इस संबंध में राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 को पारित कर दिया गया है। इससे अब बिजली की तरह पानी की दरें तय की जाएंगी। प्राधिकरण जनता की राय के बाद ऐसी दरें निर्धारित करेगा, जिससे विभाग का उपभोक्ता तक पानी पहुंचाने और मशीनरी के रख-रखाव का खर्चा निकाला जा सके।

इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि विभाग की कमियों का भार उपभोक्ता पर न पड़े। प्राधिकरण हर तीन साल में दरों की समीक्षा कर उनका पुनःनिर्धारण करेगा। राज्य जल नीति में भी प्राधिकरण के गठन का प्रावधान रखा गया है। प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो जल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन का कुशल ज्ञाता हो। *(रा.प., 30.08.13)*

किसानों के लिए सोलर पंप लाभदायक

राज्य में किसानों को 5 हॉर्स पावर के सोलर वाटर पंप लगाने की केन्द्र सरकार अनुमति देगा। अब तक केवल खेतों में सिंचाई के लिए 3 हॉर्स पावर के सोलर पंप की अनुमति है।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने जयपुर में आयोजित कार्यशाला में यह घोषणा की है। राज्य के सभी 33 जिलों में सोलर पंप सैट से सिंचाई करने का प्रयोग काफी सफल रहा है। फलस्वरूप प्रदेश में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित पंप लग रहे हैं। खेतों में इससे सिंचाई करने पर न केवल डीजल की भारी बचत हो रही है बल्कि प्रदूषण भी तेजी से कम हुआ है।

सरकार इसके लिए किसानों को 96 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है। किसान अब खेतों में बने टैंक और डिग्गियों के जरिए स्प्रिंकलर व ड्रिप आधारित सिंचाई को भी महत्व देने लगे हैं। इससे बिजली पानी और डीजल की बचत हो रही है। *(दै.भा., 29.07.13, 23.08.13)*

बदलेगा जलदाय महकमें का ढांचा

करीब 30 साल पुराना जलदाय विभाग का संगठनात्मक ढांचा अब बदलेगा। प्रदेश में अब विभाग के छह की जगह आठ मुख्य अभियंता होंगे और राजधानी में भी दो अधिक्षण अभियंता बैठेंगे। जयपुर जिले के लिए अलग से अतिरिक्त मुख्य अभियंता होगा। साथ ही हर पंचायत समिति पर सहायक अभियंता कार्यालय स्थापित किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है, जिसके तहत अभियंताओं के 817 नए पद सृजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे प्रभावी पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। जयपुर में अभी काफी कॉलोनियां ग्रामीण सर्किल में आती हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति में दिक्कत आती है। सिटी सर्किल का दायरा बढ़ने से अधिकारियों की जवाबदेहिता बनेगी। *(रा.प., 10.08.13)*

कहां हुआ टैंकरों से पानी सप्लाई?

शहर में लगातार बारिश के बाद पानी की मांग 25 से 35 फीसदी तक कम होने के बावजूद जलदाय विभाग की ओर से टैंकरों की संख्या में कमी नहीं की गई। अभी भी रोजाना 800 से 900 टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। इस पर एक दिन में करीब एक लाख रुपए से भी ज्यादा की राशि खर्च हो रही है। इससे आशंका जताई जा रही है कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है साथ ही सिटी सर्किल के इंजीनियरों की मॉनिटरिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं।

आला अधिकारियों की ओर से हर टैंकर की मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस (ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम) होने के बावजूद कई टैंकरों पर यह सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। ऐसे में इन टैंकरो से पानी कहा डाला जा रहा है, इसका विभाग के पास कोई हिसाब-किताब नहीं है।

(दै.भा.,11.08.13)

फ्लोराइड वाले गांवों को मिलेगा शुद्ध पानी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जिलों के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 723.88 करोड़ रुपए की पेयजल योजना की आधारशिला रखी।

रतलाम मोड़ पर विद्युत उत्पादन गृह प्रथम के निकट दोनों जिलों के लिए प्रस्तावित योजना के तहत दोनों जिलों के 416 गांवों में माही बांध का पानी पहुंचाया जाएगा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में काफी समय से लोग फ्लोराइड़ युक्त पानी पीने को मजबूर है। इस योजना से उन्हें मीठा और शुद्ध पानी मिल सकेगा। *(दै.भा., 30.09.13)*

झालावाड़ में बनेगा चौथा बड़ा बांध

प्रदेश की महत्वाकांक्षी परवन बांध परियोजना को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। झालावाड़ जिले में प्रस्तावित इस परियोजना पर 2360.43 करोड़ रुपए की लागत आएगी। करीब 490 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता का यह बांध राज्य का चौथा बड़ा बांध होगा। प्रदेश में सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है, उसके बाद माही और बीसलपुर का नंबर आता है।

जल संसाधन के प्रमुख सचिव ओ.पी. सैनी ने बताया कि यह बांध पांच साल में बनकर तैयार होगा। इस बांध के बनने पर एक लाख 31 हजार 400 हैक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी। साथ ही इससे झालावाड़, कोटा और बांरा जिलों के 820 गांवों में पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। *(दै.भा., 08.08.13)*

पानी व्यर्थ नष्ट करने पर जुर्माना

राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुन्दा तहसील के गांव भुटाला के वार्ड नं. 4 में पंचायत ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया है कि जो भी पानी को व्यर्थ नष्ट करेगा, उस पर 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत की उप-सरपंच लीलाबाई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पांच सदस्यों का एक दल पानी के दुरूपयोग पर निगरानी रखेगा तथा निर्णय की क्रियान्विति करेगा।

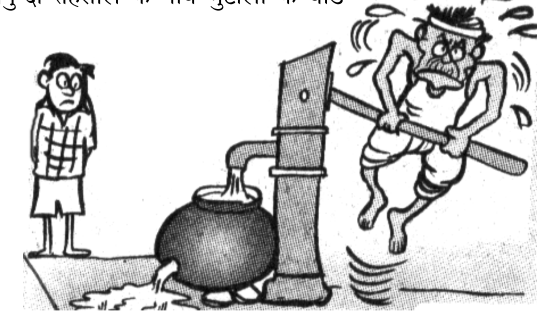

उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी के पंप स्थापित किए हैं, किंतु यह देखने में आया है कि लोग काम में लेने के बाद पंप बंद करना भूल जाते हैं और बहुत मात्रा में पानी व्यर्थ जाता है। इस संबंध में पिछले दिनों जागरूकता अभियान भी चलाया गया था, किंतु उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, इसलिए पंचायत ने जुर्माने का निर्णय किया है। *(बी.एल., 17.07.13)*

नहीं लग पाया भ्रूण हत्याओं पर अंकुश

लिंग परीक्षण के विरुद्ध कड़ा कानून बनने और प्रदेश भर में कई जगह भ्रूण परीक्षण के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश नहीं लग पाया है। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2011 से मार्च 2013 के दौरान करीब 2300 सोनोग्राफी सेंटरों की जांच में 557 खामियां पाई गई थी।

स्वास्थ्य विभाग और कई स्वयंसेवी संस्थान 'बेटी बचाओ' अभियान पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आए दिन मृत कन्या भ्रूण मिलने या जीवित नवजात कन्या मिलने के मामले सुर्खियों में रहते हैं। स्वास्थ्य महकमे की लचर व्यवस्था के चलते सोनोग्राफी सेंटरों पर समय पर जांच नहीं होने से चोरी-छिपे लिंग परीक्षण की आशंका बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि जांच व्यवस्था की कमी व खामियों का फायदा उठाकर सोनोग्राफी सेंटर संचालक लिंग परीक्षण करने से नहीं चूकते। *(रा.प., 01.08.13)*

कागजों में सिमटी सहायता समितियां

राज्य सरकार ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए 1997 में सभी जिलों में महिला समितियों के गठन के आदेश दिए थे। लेकिन पीड़ित महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए बनी महिला सहायता समितियां सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई हैं। जुल्म की शिकार महिलाओं की मदद करना तो दूर, बीते एक साल में राज्य के अधिकतर जिलों में महिला समितियों की बैठक तक नहीं हुई। धौलपुर, झालावाड़ और कुछ अन्य जिलों में तो महिला सहायता समितियां गठित ही नहीं हो पाई।

इन समितियों की अध्यक्षता का जिम्मा जिला प्रमुख के जिम्मे है। जिला कलेक्टर समिति के उपाध्यक्ष और महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक सचिव हैं। इन समितियों के गठन का उद्देश्य पीड़िताओं को विधिक एवं आर्थिक सहायता, सुरक्षा व सम्बल प्रदान करना था, लेकिन सरकारी फीताशाही के चलते इन समितियों के गठन के औचित्य पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। *(रा.प., 22.07.13)*

कुपोषण पर केन्द्र सरकार बेफिक्र

देश में कुपोषण से निपटने को लेकर केन्द्र सरकार की उदासीनता का अंदाजा इससे लग सकता है कि 2005-06 के बाद की स्थिति का अधिकारिक आंकड़ा उनके पास नहीं है। संसदीय समिति ने संसद को सौंपी अपनी रिपोर्ट में आश्चर्य जताया कि उसके पास कुपोषण के ताजा आंकड़े नहीं है।

समिति ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-4 शीघ्र कराया जाए। सर्वे हर 3 साल में सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण किया जाए। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 30 का लक्ष्य अभी दूर है, इसे हासिल किया जाए। समिति ने कहा कि बाल विकास सूची में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, औडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान पर हैं। इनमें पांच वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य व पोषण राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। *(रा.प., 10.09.13)*

परिवार कल्याण में चित्तौड़गढ़ अव्वल

राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ को अव्वल जिला घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़ और तीसरे नंबर पर झालावाड़ रहा है। परिवार कल्याण प्रोत्साहन के रूप में इन जिलों को क्रमशः 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चित्तौड़गढ़ ने 2012-13 के दौरान 9,988 नसबन्दी, 28,736 संस्थागत प्रसव और 28,144 बच्चों को पूर्ण टीकाकरण कर पहला स्थान हासिल किया।

विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में चिकित्सा राज्यमंत्री राजकुमार शर्मा ने विभिन्न जिलों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। *(दै.भा., 12.07.13)*

54 फीसदी लड़कियां एनीमिया से पीड़ित

किशोरावस्था के दौरान खून की कमी के कारण देश में 56 फीसदी लड़कियां और 30 फीसदी लड़के एनीमिया से पीड़ित है। राजस्थान में यह प्रतिशत 53.9 व 33 फीसदी है। यह जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयपुर में आयोजित मीडिया कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉ. समित शर्मा ने कहा कि आयरन फोलिक ऐसिड एनीमिया दूर करने में उपयोगी साबित होगी।

कार्यशाला में चिकित्सा विभाग के आईईसी निदेशक व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. रविकुमार सुरपुर एवं यूनिसेफ के राजस्थान प्रमुख सैमुअल सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी इस समस्या के निवारण की जरूरत बताई। *(रा.प., 03.08.13)*

गिलास अभी भी आधा खाली

देश की आधी आबादी यानि महिलाओं के हक की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। दामिनी के हत्यारों को फांसी की सजा होने के बाद महिला अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि समय के साथ भारतीय परिवारों में महिला सुविधाओं की संख्या बढ़ी है, हालांकि एक सच यह भी है कि ऐसे परिवारों की समृद्धि का आंकड़ा बेहद कम है। यानि अभी भी आधा गिलास खाली है।

अभी भी देश में महिलाओं को मिलने वाले वेतन या मजदूरी में भेदभाव रखा जाता है। महिलाओं को अभी तक पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक नहीं मिल सका है। लोकसभा व विधानसभाओं में 50 फीसदी आरक्षण भी नहीं मिल सका है। महिलाएं प्रायः उन परिवारों में ही मुखिया होती है, जहां पुरुष मुखिया की मृत्यु हो गई हो, इससे उनकी आमदनी पर इसका गहरा असर होता है। *(रा.प., 15.09.13)*

स्कूलों में है शिक्षकों की कमी

राज्यपाल मार्ग्रेट अल्वा ने प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में 70 हजार स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चो के लिए आठ हजार स्कूलों में पेयजल सुविधा और 15 हजार स्कूलों में टॉयलेट सुविधा नहीं है। जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि गांवों में शिक्षक काम नहीं करना चाहते। स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति का प्रतिशत भी बहुत अधिक है।

शिक्षा मंत्री बृज किशोर शर्मा व प्रमुख शासन सचिव शिक्षा वीनू गुप्ता ने भी माना कि प्राईमरी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महामहिम की बातों में काफी सच्चाई है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है । आधारभूत सुविधाओं की कमी को भी जल्द दूर किया जाएगा। *(दै.भा., 06.09.13)*

सड़क सुरक्षा

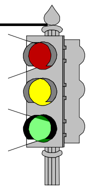

क्यों टूट जाती हैं शहर की सड़कें?

नगर निगम और जेडीए की सड़कें एक ही बारिश या बनाने के ठीक बाद ही क्यों टूट जाती है। यह आमजन के लिए भले ही एक पहेली हो, लेकिन इसके पीछे बड़ा घालमेल है। शहर की ज्यादातर सड़कों के बनाने के लिए हर बार टेंडर गिने चुने 10 से 15 ठेकेदारों के नाम पर ही खुलते हैं। छोटे-मोटे मिलाकर कुल 50 से ज्यादा ठेकेदार सड़कों के काम देख रहे हैं, लेकिन बड़ी 138 सड़कों का काम हर बार उन्हीं ठेकेदारों को मिल रहा है, जिनकी जेडीए या निगम से लेकर सरकार तक पहुंच है।

इन ठेकेदारों द्वारा बनाई गई सड़कों पर सवाल खड़ा होते ही अफसर ढाल बन जाते हैं और यही जवाब मिलता है कि इनसे बेहतरीन कोई ठेकेदार है ही नहीं। रोड टूटने की तो कई वजहें होती है। पिछले 10 साल में एक ही ठेकेदार को एक से ज्यादा और कुछ को तो 8 से 10 सड़कों तक के ठेके देने के मामले बढ़ गए हैं। जेडीए हर साल सड़क निर्माण और नवीनीकरण पर करीब 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसी तरह नगर निगम भी हर साल करीब 150 से 200 करोड़ रुपए रोड निर्माण और पेच वर्क पर खर्च करता है। इसके बावजूद कोई सड़कें ज्यादा समय के लिए नहीं टिकती।

सर्वविदित है कि सड़क निर्माण और मरम्मत में जमकर घालमेल होती आई है। अफसर की मिलीभगत के चलते करोड़ों के ठेके चहेती कंपनियों को दे देते हैं। कंपनियां मनमाना काम करती हैं और मॉनिटरिंग करने वाले इंजीनियर इनकी गड़बड़ियों को नजरअंदाज करते हैं। इंजीनियरों के मार्फत ही इन कंपनियों को साल दर साल काम दिया जाता रहा है। *(दै.भा., 20.09.13)*

पर्यावरण

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान पर संभाग स्तरीय कार्यशालाएं सम्पन्न

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कट्स संस्था को राजस्थान के लिए रीजनल रिसोर्स ऐजेंसी (आर.आर.ए.) नियुक्त किया गया है। इस वर्ष भी कट्स द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान राज्यभर में संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत मंत्रालय द्वारा इस वर्ष का विषय 'जैव विविधता संरक्षण' रखा गया है।

विषय के तहत प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाएं 10 नवम्बर, 2013 से 20 फरवरी, 2014 तक जागरूकता गतिविधियां एवं भौतिक कार्य अपने-अपने क्षेत्रों में करेंगी। कार्यक्रम के तहत 31 जुलाई, 2013 से 05 अगस्त, 32013 तक संभागीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 31 जुलाई 2013 को उदयपुर संभाग, 01 अगस्त, 2013 को कोटा संभाग, 02 अगस्त, 2013 को बीकानेर संभाग तथा 03 अगस्त, 2013 को जोधपुर संभाग की कार्यशालाएं आयोजित की गई।

05 अगस्त, 2013 को जयपुर संभाग की कार्यशाला में राजस्थान राज्य जैव विविधता संरक्षण बोर्ड के वन संरक्षण अधिकारी रविन्द्र भार्गव ने कहा कि पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण में स्वयं सेवी संस्थाओं का बहुत योगदान है।

उन्होंने कहा कि वनों के माध्यम से जहां हमें औषधि व फलों के अलावा बहुत से पदार्थ प्राप्त होते हैं, वहीं इनके माध्यम से आजीविका की पूर्ति भी होती है। हमें पेड़-पौधे, जानवरों और पक्षियों की विलुप्त होती प्रजातियों के विषय में ज्ञान होना चाहिए तथा इनके संरक्षण का भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी अमूल्य धरोहर है। भारत सरकार के इस अभियान का मकसद भी यही है कि समाज के सभी वर्ग अपनी भागीदारी निभाएं क्योंकि भविष्य के लिए हमें स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। इन सभी कार्यशालाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने जैव विविधता संरक्षण पर अपने-अपने अनुभवों को विस्तार से बताया।

जन स्वास्थ्य

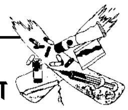

मुख्यमंत्री सहायता कोष का पैसा निजी अस्पतालों को

गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी जाने वाली सहायता राशि में से 60 फीसदी पैसा निजी अस्पतालों को जा रहा है। पिछले 15 वर्षों में सरकार निजी अस्पतालों को 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सहायता इस कोष से दे चुकी है। राज्य सरकार ने यह पैसा ज्यादातर उन निजी अस्पतालों को दिया है जिन्हें सरकार रियायती दरों पर जमीनें और अन्य रियायतें भी दी है। कैंसर, हृदय रोग और गुर्दे से संबंधित जटिल बीमारियों के इलाज के लिए हर माह औसतन 250 लोगों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 40 हजार रुपए से लेकर 60 हजार रुपए तक की सहायता राशि दी गई। इन मामलों में जो सहायता दी गई उनमें 60 प्रतिशत से भी ज्यादा मरीज निजी अस्पतालों के हैं।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई सहायता के पिछले 15 साल के मामलों की पड़ताल में यह खुलासा हुआ है। सरकार जिन निजी अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन देती है, उन्हें इसी शर्त पर जमीन दी जाती है कि वे गरीब व बीपीएल मरीजों का इलाज मुफ्त करेंगे। राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष वी.एस.व्यास का मानना है कि निजी अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन देने के लिए गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति के लोगों का मुफ्त इलाज का कोटा तय होता है। इसे देखने वाला कोई नहीं है कि इसका पालन होता है या नहीं। इसके लिए सरकार को रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। *(दै.भा., 01.09.13)*

निवेशक शिक्षा

सेबी को मिले जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के हाथ अब और भी मजबूत कर दिए गए हैं। इसके तहत सेबी को अब तलाशी, व संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी करने की इजाजत दे दी गई है। इसी तरह सेबी अब डिफॉल्टरों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दे सकेगा। इसके साथ ही सेबी को 15 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों के बारे में देश-विदेश के अन्य नियामकों से आवश्यक जानकारी मांगने की भी इजाजत दी गई है।

इससे जाहिर होता है कि सेबी पुराने मामलों को भी आसानी से खंगाल कर दोषी लोगों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रतिभूति कानून संशोधन अध्यादेश में किए गए बदलाव को पिछली तारीख से प्रभावी किया गया है। इसके तहत वे कंपनियां व लोग अपने लंबित मामलों का निपटारा कर सकेंगे जिनकी जांच सेबी द्वारा की जा रही है। सेबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले लोगों और कंपनियों के बैंक खातों व संपत्तियों को जब्त करने की भी अनुमति अब बाजार नियामक को दे दी गई है। सेबी अब अपनी जांच के सिलसिले में जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति, बैंक और प्राधिकरण वगैरह से आवश्यक जानकारी मांग सकता है। *(दै.भा., 18.07.13, 23.07.13)*

उपभोक्ता फैसले

चिकित्सक पर एक लाख रुपए का जुर्माना

झालावाड़ जिले के ख्वाजू मोहम्मद ने एस.के.चिकित्सालय के चिकित्सक इकबाल खान के खिलाफ उपभोक्ता मंच, झालावाड़ में परिवाद दर्ज कराया। इस परिवाद में ख्वाजू मोहम्मद ने मंच को बताया कि उन्होंने 20 फरवरी, 2011 को अपनी 7 माह से गर्भवती पत्नी नजमा को उपचार के लिए एस.के. अस्पताल में भर्ती कराया था। इस निजी चिकित्सालय में उनकी पत्नी का उपचार चिकित्सक इकबाल खान ने किया। इसके बदले में उनसे 30 हजार रुपए वसूले गए। लेकिन गलत उपचार के कारण उनकी पत्नी के गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई। उन्होंने मंच के सामने अपनी पत्नी और गर्भस्थ शिशु के इलाज में चिकित्सक द्वारा बरती गई लापरवाही को उजागर किया।

मंच ने सुनवाई पर ख्वाजू मोहम्मद के बयानों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सक द्वारा बरती गई लापरवाही और गलत उपचार को गंभीर सेवा दोष माना। मंच ने चिकित्सक इकबाल खान को आदेश दिया कि वह ख्वाजू मोहम्मद को एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति व एक हजार रुपए परिवाद खर्च के रूप में अदा करे।

(रा.प., 07.07.13)

गलत ऑपरेशन किया, ढाई लाख रुपए का जुर्माना

उदयपुर जिले के पानेरियों की मादड़ी निवासी हर्षवर्धन मेनारिया ने स्थाई लोक अदालत में परिवाद दर्ज कराते हुए बताया कि उसने गाल ब्लेडर में पथरी की तकलीफ होने पर 29 जनवरी, 2010 को हिरणमगरी के सैटेलाइट अस्पताल में डॉ. एस.के. सामर से ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन के दौरान एक महत्वपूर्ण नली कट जाने से अत्यधिक रक्तस्त्राव हुआ था। उसकी हालत खराब होने पर डॉ. सामर महाराणा भूपाल अस्पताल ले गए थे, जहां उसे भर्तीकर उपचार किया गया था।

इलाज में विशेष लाभ नहीं मिलने पर परिजन उसे अहमदाबाद ले गए थे। जहां ऑपरेशन व दो माह के इलाज के बाद उसकी तबियत में सुधार हुआ। लोक अदालत ने डॉ. सामर व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दोषी मानते हुए पीड़ित युवक को ढाई लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

(दै.भा., 06.07.13)

खास समाचार

कट्स का अफ्रीका में तीसरे केन्द्र का शुभारंभ

कट्स इंटरनेशनल ने अनेकों अफ्रीकी देशों में बड़े पैमाने पर व्यापार व विकास, प्रतिस्पर्धा, नियामक नीति तथा उपभोक्ता संरक्षण के मुद्दों पर कार्य किया है। हाल ही कट्स का अफ्रीका में तीसने केन्द्र का शुभारंभ किया गया है। इस नए केन्द्र के माध्यम से कट्स व्यापार एवं विकास पर दक्षिण-दक्षिण को बढ़ावा देने की अपनी नीति को मजबूती दे सकेगा एवं क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक एवं विकासशील चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इसे और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

उद्घाटन के मौके पर घाना के विदेशी मामलात एवं क्षेत्रीय एकीकरण मंत्री हन्ना टेटे ने कहा कि हम अफ्रीकी देश घाना की राजधानी आकरा में कट्स के नए केन्द्र का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नया केन्द्र घाना एवं पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी निभाने में अपनी भूमिका निभाएगा। कट्स ने सफलता पूर्वक ग्रासरूट को शोध एवं पैरवी तथा नेटवर्किंग के माध्यम से नीति निर्धारकों को जोड़ने की पद्धति विकसित की है।

यह केन्द्र अफ्रीका में एक विचारशील एवं कार्यवाही समूह के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा। कट्स का अफ्रीका महाद्वीप में पहला केन्द्र जाम्बिया की राजधानी लुकासा में तथा दूसरा केन्द्र केन्या की राजधानी नैरोबी में वर्ष 2000 तथा 2002 से संचालित हैं।

अलग से उपभोक्ता मंत्रालय के गठन का निर्णय सराहनीय कदम

राजस्थान में उपभोक्ता हितों की रक्षार्थ राज्य सरकार अलग से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के गठन पर सहमत हो गई है। इसके लिए राज्य केबिनेट द्वारा 7 सितम्बर, 2013 को लिया गया फैसला सभी उपभोक्ता आंदोलनकारियों की जीत है।

'कट्स' संस्था लंबे समय से इस बाबत राज्य सरकार के समक्ष यह मुद्दा उठाती रही है। उपभोक्ता संस्थाओं के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ बजट पूर्व हुई बैठक के दौरान भी कट्स द्वारा इस बाबत पुरजोर मांग उठाई गई थी और केरल और जम्मू कश्मीर का उदाहरण भी दिया गया था। हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा फैसला लेना अभी बाकी है।

उपभोक्ता मामलात का अलग सें विभाग बनने पर बांट-माप, खाद्य एवं औषधि निरीक्षण जैसे कई मामले एक ही छत के नीचे आ जाएंगे, इससे आपसी सामन्जस्य व उपभोक्ताओं की सीधी पहुंच आसान हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला निश्चित तौर पर उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करेगा।

काला बाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि उपभोक्ता को समय पर खाद्य सामग्री का वितरण करने में लापरवाही बरतने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएं। उन्होंने अपने आवास पर खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ खाद्य सामग्री वितरण व राशन कार्ड वितरण की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान उचित मूल्य की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करने तथा वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री की निगरानी करने के लिए भी जरूरी निर्देश दिए हैं।

(रा.प., 09.09.13)

स्त्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, बी.एल.: बिजनेस लाइन

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।